बाइबल भी है और देश में इलेक्ट्रिसिटी की कमी भी है, तो क्या सरकार इस कमी की पूर्ति करने के लिए टाइडल वेव्ज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देश को देने के बारे में सोचेगी?

श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ: मेरी तो नोन कन्वेन्शल एनर्जी से बहुत सहानुभूति है। मैं तो माननीय सदस्य से कहूंगा, उनको राय दूंगा कि वह मेरे सहयोगी मंत्री कैप्टेन निषाद से यह सवाल पूछें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think this question of power generation is very important and if the members so feel...

SHRI SATISH AGARWAL: There should be a healf-an-Hour Discussion on this.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have taken more than half-an-hour on it today in the question Hour. But you cannot discuss the entire power crisis—I don't mean the political power, I mean the electricity—in the country. We should have a full-fledged discussion on it. If the Members so agree, we can discuss it in the Business Advisory Committe.

SHRI SATISH AGARWAL: Yes, Madam, we should have a discussion.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: I would be very happy, Madam, for a full discussion because that would support...

THE DEPUTY CHAIRMAN: So, we will discuss it today in the Business Advisory Committee and in the next week perhaps...

SHRI SATISH AGARWAL: It would be more advisable if the Minister gives us the last position with regard to power and if that paper is circulated to the Members, it will become a very structured debate. You can give a working paper on the power scenario.

SHRI YOGINDER K. ALAGH: We will be very happy to circulate a very detailed paper for such a discussion.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I want to know whether it will be discussed through a Short Duration Discussion or a Calling Attention Montion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Whichever way we decide; but I think there should be a full-fledged discussion because living in Delhi if we are thrown into darkness, at least you can throw some light even with a candle.

Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

गेहूं की खुली बिक्री पर सरकार द्वारा प्रतिबंध

*64. **श्री रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गेहूं की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और प्रतिबंध की अवधि क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा गेहूं की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी भारतीय खाद्य निगम व्यापारियों को गेहूं बेच रहा है;

(घ) यदि हां, तो निगम के किस गोदाम से कब-कब कितना गेहूं बेचा गया और इस अवैध बिक्री से भारतीय खाद्य निगम को कितने रुपये का घाटा हुआ; और

(ङ) प्रतिबंध के बावजूद गेहूं बेचने में लगे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इस घाटे को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी?

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय पूल में गेहूं का कम स्टाक होने के कारण खुले बाजार में बिक्री योजना पहली अप्रैल, 1997 से अगले आदेश होने तक समाप्त कर दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।